Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 13, Issue No. 2, July-2017, ISSN 2230-7540

वर्तमान शिक्षा के सामाजिक दुष्परिणाम एवं सुधार हेतु चिंतन

Kamla*

Research Scholar

सारा – वर्तमान शिक्षा की बात करें तो उसे लेकर हमेशा ही एक ठोस और बेहतर शिक्षा नीति की कमी खलती रही है, वर्तमान शिक्षा का दायरा ज्ञान से अधिक व्यवसायिकता के रुप में रेखांकित किया जा सकता है। वर्तमान शिक्षा के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्ष हैं लेकिन नकारात्मक पक्ष इसे हमेशा ही हाशिये पर धकेलते रहे हैं...। ये शिक्षा अभिभावकों के लिए एक भारी–भरकर बोझ अधिक है, महंगी होने के बावजूद हमारी शिक्षा व्यवस्था आम अभिभावकों को ये भरोसा नहीं दिलवा पा रही है कि वो उसके भविष्य के लिए एक उत्तरोतर राह तलाश पाएगी...। अब तक की शिक्षा नीतियों की बात करें तो वे समयानुकूल सुधार को लेकर बनाई गई लेकिन उनसे दूरगामी कोई ऐसे सुधार नजर नहीं आए जिससे ये माना जाए कि हम एक बेहतर, सुगम और सराहनीय शिक्षा नीति का हिस्सा हैं।

----------X----------

प्रस्तावना

शिक्षा नीति पर सारगर्भित मंथन की आवश्यकता है। अभिभावकों की मानें तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली से हम अपने बच्चों को दौड़ का एक हिस्सा बना रहे हैं, हम उन्हें धावक की तरह भारी–भरकम शिक्षा के साथ बड़ा करते हैं। हमें ये भी सोचना होगा कि आखिर हम आदर्श शिक्षा व्यवस्था किसे मानते हैं, मुझे लगता है वर्तमान शिक्षा हमें केवल ज्ञान तो दे रही है लेकिन आदर्श नहीं दे रही। शिक्षा में संस्कार, संस्कृति, प्रकृति और कौशल भी समाहित होना चाहिए। हम अपनी पुरातन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को देखें तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि ये सभी तत्व उसका हिस्सा थे यही कारण था कि उस समय में हम गहरे और प्रभावी व्यक्तित्व पाते हैं। हमारी वर्तमान शिक्षा दो खंडों में विभाजित हो गई है। एक सरकारी तौर पर दी जाने वाली वो पुरानी ढर्रे वाली शिक्षा और दूसरा चेहरा निजी स्कूलों में देखा जा सकता है। कुछेक उदाहरण छोड़ दिए जाएं तो अमूमन स्कूल केवल वही शिक्षा दे रहे हैं जो हमें केवल ज्ञान दे रही है, संस्कार तो कोसो दूर हैं। यही कारण है कि हम अपने भारतीय परिवेश की पहचान वाले समग्र परिवारों से खंड–खंड विभाजित होकर एकल होते जा रहे हैं। शिक्षा हमें केवल शिक्षित न करे वो हमें मानवीय और एक अच्छा इंसान बनने में मददगार हो।

शिक्षा सदैव गतिमान रहने का विषय है, ये युग और काल के अनुरुप बदलती रही है, शिक्षा का स्वरुप भी बदला है और उसकी नीतियों में भी समय–समय पर परिवर्तन आया है। शिक्षा की नीतियां देशकाल और समय के अनुरुप अपने आप को ढालती रही हैं, लेकिन ये पूरी तरह से पूर्ण अवस्था में न कभी रही है और न ही कभी हो पाएंगी इसमें सुधार और परिवर्तन के अंश जुड़ते रहेंगे और यही इस प्रकृति का भी नियम है। हम शिक्षा को हर काल में श्रेष्ठ पाते हैं लेकिन वो अगले काल में उससे भी अधिक परिष्कृत होकर सामने आती है। नीतियों पर बात करें तो ये कालखंड के अनुरुप तैयार हुईं और इनमें भी आंशिक अथवा समूल बदलाव आए हैं लेकिन इसका ये आशय भी कतई नहीं है कि शिक्षा हमारे में नैतिक और संस्कारपरक गुण परिष्कृत करने में अब पूरी तरह ही अक्षम हो चुकी है, हां अब शिक्षा को इस तरह कोई भी देखना पसंद नहीं कर रहा है। सब सिस्टम का हिस्सा हो जाने के लिए केवल नौकरी की दौड़ अनिवार्य है लेकिन संस्कार भी पीछे नहीं छूटने चाहिए। शिक्षा हर काल में हमें बेहतर नजर आई है और हम उसके अनुसार बेहतर होते गए और उसी में से उसके सुधार की नई धाराएं भी प्रस्फुटित भी हुई हैं। शिक्षा नीति को हम बहुत ही विस्तृत तौर पर समझ सकते हैं और इसकी समय–समय पर शिक्षाविदों ने व्याख्याएं भी की हैं, हम बेहतर शिक्षा उसे कहते आए हैं जो हमें सफलता के पथ तक पहुंचाए या हमें वो जिंदगी जीने के लायक बना पाए, लेकिन इसे लेकर मेरा मत है कि शिक्षा यदि केवल शिक्षित कर रही है तो मुझे इसमें बड़े से सुधार की गुंजाईश नजर आती है। मैं एक बार फिर अपनी बात पुरजोर तरीके से उठाना चाहती हूं कि शिक्षा केवल शिक्षित न करें वो हमें संस्कारवान और एक सुलझे हुए विचारों से परिपूर्ण होने में मददगार साबित हो। शिक्षा केवल धनोपार्जन का केंद्र बिंदु बनकर रह गई है। एक बात जो हम अपनी वर्तमान शिक्षा नीति में महसूस कर रहे हैं वो ये कि अब हम केवल अंकों की एक दौड़ का हिस्सा हैं, हमारे बच्चों का लक्ष्य केवल अंकों की श्रेष्ठता पर ही आधारित होकर रह जाता है। ये अंक उन्हें एक ऐसे संघर्ष का हिस्सा बना देते हैं जिनमें उनका वैचारिक विकास बाधित होना शुरु हो जाता है। अंकों की भीड़ में हम एक ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं जो जीत तो रहा है लेकिन उसे ये नहीं पता कि दौड़ में उसने आखिर क्या कुछ दांव पर लगा दिया है। हमारी शिक्षा नीति उसे बेहतर बनाने के लिए उस अंकों की जकड़न से बाहर नहीं निकल पा रही है। अब हम अपनी इस शिक्षा नीति को संस्कारपरक शिक्षा से चाहकर भी नहीं जोड़ पा रहे हैं क्योंकि अब एक दौड़ है जो तेज और दिनोंदिन तेज होती जा रही है। हम संस्कारपरक और ज्ञानवर्धक शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं, इसका सीधा असर समाज पर परिलक्षित हो रहा है। समाज का चेहरा हमारे सामने है वो मोहक है लेकिन मन को सुकून और राहत देने वाला नहीं है।

हम अगर शिक्षा नीतियों का तुलनात्मक अध्ययन एवं गुणवत्तापरक शैक्षिक सुधार पर गहन अध्ययन करें तो ये बेहतर

तरीके से समझ पाएंगे कि समय और युग शिक्षा में सुधार के अहम हिस्से साबित होते हैं, हर युग गुणवत्तापरक शिक्षा पर जोर देता आया है और ये वर्तमान में और अधिक परिष्कृत रुप में नजर आ रहा है। हम ये बात स्पष्ट तौर पर मानते हैं कि ये कौशल विकास का युग है और इसमें हम शिक्षा में केवल ज्ञान तक सीमित नहीं हो सकते हैं इसे और अधिक सारगर्भित तौर पर समझकर बेहतर बनाने की दिशा में कार्यो की आवश्यकता है। शिक्षा नीतियों की तुलना की हम बात करें तो ये हमें समय के अनुसार बेहतर होती नजर आती हैं, ये इसका व्यवहारिक स्वरुप भी माना जा सकता है। हमें शिक्षा के व्यवहारिक पक्ष के साथ ही उसके संस्कारपरक होने और ज्ञान के समग्र को जानने के काबिल कैसे बनाया जा सकता है इस पर काम करना होगा। हम शिक्षा की एक और नई नीति की वकालत करते हैं क्योंकि आधुनिक युग में अब इसका वो पुराना स्वरुप रास नहीं आ रहा, इसे वर्तमान दौर के अनुरुप बनाने के लिए कई अहम परिवर्तन होने चाहिए। ये शिक्षा वो हो जो हमें ज्ञान के साथ अपने आप से परिचित करवाने की क्षमता रखती हो।

हम जब भी शिक्षा की बात करते हैं तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी वो आबादी भी नजर आती है जिसके लिए शिक्षा सुगम तौर पर मुहैया होना चाहिए लेकिन आजादी के इतने सालों के बावजूद भी ये नहीं हो पाया है। ये बात कतई नहीं है कि सरकारी तौर पर इसके लिए प्रयास नहीं हुए लेकिन सरकारी प्रयासों को अमलीजामा पहनाने में जो समय लगता है उससे व्यवस्था में कोई सुवासित सुधार नजर नहीं आया। हम वर्तमान शिक्षा की स्थितियों, उसकी चुनौतियों के अलावा अभिभावकों पर आर्थिक बोझ के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, हम ये भी देखेंगे कि वे कौन से विषय हैं जो इस व्यवस्था को सुधारने में अहम भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। हमने इसे तह तक समझने की कोशिश की है और इसके लिए उप्र के बरेली मंडल का चुनाव किया। इस मंडल में आने वाले हिस्से में शिक्षा के वर्तमान स्वरुप पर बात हुई और अभिभावकों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ पर चर्चा हुई जिनमें बहुत कुछ बेहतर बिंदु रेखांकित हुए हैं।

अनुसंधान विधि एवं मंडल का विवरण–

उक्त विषय पर आमने–सामने साक्षात्कार की विधि का प्रयोग करते हुए सामान्य जनमानस की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर उनकी सामाजिक, मानसिक व आर्थिक स्थिति के संबंध में विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। जैसा कि ज्ञात हो बरेली मंडल की कुल जनसंख्या 16015103 है जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 8410966 एवं महिलाओं की जनसंख्या 7604137 है। उक्त मंडल में कुल 8064215 लोग ही साक्षर हैं जबकि 7950888 लोग अब भी निरक्षर हैं। उक्त समस्त आंकड़े भारत की जनगणना 2011 से लिए गए हैं जिनको भारत सरकार द्वारा www.censusindia.gov.in पर प्रदर्शित किया गया है। उक्त आंकड़े वास्तव में चौंकाने वाले हैं। यदि किसी मंडल के लगभग 50प्रति''ात लोग निरक्षर हैं तो निश्चित रुप से हमारी शिक्षा व्यवस्था उनकी पहुंच से दूर है। कारण सामाजिक भी हो सकते हैं, आर्थिक भी हो सकते हैं या अन्य। उक्त आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए जिज्ञासावश **'वर्तमान शिक्षा के सामाजिक दुश्परिणाम एवं सुधार हेतु चिंतन'** करने का निर्णय लिया गया। आमने–सामने साक्षात्कार के माध्यम से उपलब्ध अहम बिंदुओं को उक्त शीर्षक एक विषय के अंतर्गत लिखा गया है।

क्रम संख्या	बरेली मंडल के जनपद	जनसंख्या (जनगणना 2011 के अनुसार)		
		कुल	पुरुष	महिला
1	मुरादाबाद (संभल सहित)	4772006	2503186	2268820
2	बरेली	4448359	2357665	2090694
3	रामपुर	2335819	1223889	1111930
4	बिजनौर	3682713	1921215	1761498
5	अमरोहा	776206	405011	371195
	संपूर्ण योग	16015103	8410966	7604137

क्रम संख्या	बरेली मंडल के जनपद	साक्षर			निरक्षर		
		कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
1	मुरादाबाद (संभल सहित)	2263848	1357435	906413	2508158	1145751	1362407
2	बरेली	2191759	1342697	849062	2256600	1014968	1241632
3	रामपुर	1043666	630408	413258	1292153	593481	698672
4	बिजनौर	2135393	1241471	893922	1547320	679744	867576
5	अमरोहा	429549	256825	172724	346657	148186	198471
	संपूर्ण योग	8064215	4828836	3235379	7950888	3582130	4368758

वर्तमान शिक्षा के सामाजिक दुष्परिणाम एवं सुधार हेतु चिंतन के संबंध में हमने बरेली मंडल के बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, बिजनौर जनपदों के कुछ हिस्सों में पहुंचकर बात की। इसमें अधिकांश अभिभावकों ने सीधे तौर पर शिक्षा की नीति के पुराने से ढर्रे में सुधार की आवश्यकता की बात उठाई है। यहां कुछ अभिभावकों से हुई बातचीत से हमें ये बात साफ हो जाती है कि वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था में अभिभावक सहज नहीं हैं, वे एक प्रक्रिया का हिस्सा हो रहे हैं।

– बरेली निवासी और रेलवे फार्मासिस्ट अमित कुमार का कहना है कि शिक्षा का वर्तमान चेहरा उन्हें कतई खुश नहीं कर रहा है, बच्चों को पढ़ाना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। सरकारी स्कूल हैं लेकिन वर्तमान शिक्षा का जो चेहरा है वो अंग्रेजी के गहरे से अवसाद का हिस्सा है। ये कैसा दौर है कि अंग्रेजी के बिना हम अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। सरकारी स्कूल हैं वहां शिक्षा सस्ती है लेकिन पढ़ाई का स्तर उन स्कूलों में कभी भी उच्चस्तरीय मापदंडों को प्राप्त नहीं कर पाया। निजी स्कूल मनमाफिक फीस वसूल रहे हैं, पढ़ाई दिनोंदिन महंगी होती जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में अभिभावक बच्चों को कर्ज लेकर पढ़ाते हैं वे इस उम्मीद में उस पर खर्च करते हैं कि उसका भविष्य बेहतर बनेगा लेकिन दुख इस बात का है कि वो दौड़, वो महंगाई उच्च शिक्षा की ओर बढ़ने के दौरान तेजी से बढ़ती जाती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान की ये महंगी शिक्षा उन्हें इस बात का दिलासा नहीं दिलवाती कि उनके बच्चे का भविष्य सुरक्षित है। शिक्षा हमें एक बेहतर इंसान बनने की राह बताती है, लेकिन ये मंहगाई, ये बाजार, ये वही सालों पुराना ढर्रा कोई उम्मीद नहीं बंधाता। उन्होंने बताया कि जिस घर में दो बच्चे हैं उस घर के अभिभावक यदि आर्थिक तौर पर कमजोर हैं तो वे अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, कोई हिम्मत भी करता है तो वो कर्ज का जाल उन्हें पूरी तरह ढांक लेता है। देश में सस्ती शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और शिक्षा के वर्तमान स्वरुप में भी बदलाव होना चाहिए, हमारी शिक्षा बेशक बच्चों को बेहतर और विस्तृत ज्ञान दे रही है लेकिन उनमें संस्कार और व्यवहार नदारत हैं।

बरेली के नवेद, ओमप्रकाश सिंह का भी मानना है कि शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, वो समाज के हर वर्ग के लिए आसानी से मुहैया हो। साथ ही उन्होंने शिक्षा में नैतिक शिक्षा को अनिवार्य और बेहतर तरीके से शामिल करने की बात पर भी जोर दिया।

– रामपुर निवासियों से भी चर्चा हुई। उन्होंने शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर बेबाकी से अपनी बात कही। कुछ लोगो का कहना था

कि वर्तमान शिक्षा का सकारात्मक पक्ष ये है कि वो दुनिया से जोड़ने की ताकत रखती है लेकिन इसका सबसे बड़ा नकारात्मक पक्ष ये है कि इतनी महंगी है कि आम व्यक्ति की पहुंच से ये अब दूर होती जा रही है। बच्चों को पढ़ाने में अभिभावक कर्जदार हो रहे हैं...बावजूद इसके आशानुरुप परिणाम नहीं आ रहे हैं...। उनका मानना है कि निजी स्कूलों में अधिक सुविधाएं ही अभिभावकों का ध्यान खींचती हैं, ये सुविधाएं यदि सरकारी स्कूलों में मुहैया हो जाएं और शिक्षा का बिगड़ा हुआ ढर्रा यदि सुधर जाए तो काफी कुछ बेहतर हो सकता है। उनका कहना है कि हम वर्तमान शिक्षा से बेहतर की उम्मीद करते हैं और यही कारण है कि अपनी आर्थिक स्थिति से अधिक खर्च कर देते हैं लेकिन दुख की बात ये है कि अभिभावकों को ये महसूस होने लगा है कि हमारे देश में शिक्षा जो कभी ज्ञानार्जन का मुख्य केंद्र होती थी अब एक कारोबार जैसा चोला ओढ़ चुकी है। इसे सस्ता करने के लिए सरकार को कोई ठोस पहल करनी चाहिए।

मुरादाबाद निवासी बालादत्त शर्मा का स्पष्ट कहना था कि वे वर्तमान शिक्षा से कतई खुश नहीं हैं, उन्हें ये नहीं लगता कि हमारी ये शिक्षा और व्यवस्था सही हैं। अपनी पुस्तक **'आओ देश गढें'** का जिक्र करते हुए कहा कि वे इस शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की गुंजाइश देखते हैं और शिक्षा व्यवस्था में सुधार को रेखांकित करते हुए आदर्श शिक्षा नीति को लेकर सुझावों को अपनी किताब में स्थान दिया है। उन्होंने कहा कि जब छोटे थे तब सोचा करते थे कि हमसे कभी किसी ने नहीं पूछा कि तुम जीवन में क्या करना चाहते हैं? मुझे लगता है माता–पिता से अधिक ये पूछने की जिम्मेदारी शिक्षक और व्यवस्था के हिस्से आती है। शिक्षा के दरवाजे तब भी संकरी सी व्यवस्था के कारण जाम थे और अब तो वो चरमाने की स्थिति तक आ पहुंचे हैं। दुख इस बात का है कि आज भी बच्चों से ये नहीं पूछा जा रहा है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो? शिक्षा को लेकर हालात बहुत बेहतर नहीं कहे जा सकते। हमारे देश में शिक्षा रुचि के लिए नहीं बल्कि नौकरी के लिए अर्जित की जाती है। शहरों और गांवों की तुलना करें तो अंचल में हालात और अधिक खराब हैं क्योंकि वहां के बच्चे जो महंगी शिक्षा अर्जित करने शहर तक जाते हैं लेकिन यहां के खर्च उन्हें आर्थिक तौर पर कमजोर बना देते हैं। क्या हमें नहीं लगता कि हम एक मशीन के पुर्जे बन चुके हैं...ये शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था ज्ञान तो दे रही है लेकिन जो तरीका ज्ञान देने का अपनाया जा रहा है उसमें सुधार होना नितांत आवश्यक है। उनका कहना है कि मेरे विचार से रुचिकर शिक्षा और पारदर्शिता पूर्ण निष्पक्ष शिक्षा से ही श्रेष्ठ चिंतन और श्रेष्ठ समाज की अवधारणा को स्थापित किया जा सकता है। उनका कहना था कि बेहतर शिक्षा ही देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर सकती है, सभ्यता में नैतिकता का संचार कर सकती है। पीढ़ियों को निखार सकती है। शिक्षा केवल मजबूरी न हो, वो ज्ञान अर्जन के रुप में स्वीकारी जानी चाहिए। उसे सस्ती और सुलभ बनाने की दिशा में ईमानदार कोशिशें होनी चाहिए।

मुरादाबाद निवासी दीपक कुमार कहना है कि वर्तमान शिक्षा में खामियों के साथ ही बहुत से बेहतर पक्ष भी हैं लेकिन ये शिक्षा महंगी होने के कारण ही अभिभावकों के लिए मुश्किल बनती जा रही है। इसमें सुधार के लिए हर ओर से प्रयासों की आवश्यकता है। उनका कहना है कि सरकारी स्कूल अब भी उसी पुराने से ढर्रे पर चल रहे हैं उनमें बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है क्योंकि अब भी हमारे देश में बड़ी आबादी इन्हीं सरकारी स्कूलों पर निर्भर है। यहां के तौर–तरीके सुधरने चाहिए। उन्होंने मिड डे मील योजना पर भी सवाल उठाए और कहा कि इस तरह बच्चों का स्कूलों तक आना न तो संभव है और न ही एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा। इस योजना से हम बच्चों को स्कूल में खींच भी लें तो वे भोजन बनने तक ही स्कूल में ठहर पा रहे हैं, उनका पूरा ध्यान भोजन की ओर ही रहता है। बेहतर होता कि इस योजना की जगह बच्चों को पढ़ने की सामग्री, गणवेश और अच्छी किताबें तथा बेहतर माहौल मुहैया करवाया जाता। वे इस बात को भी बेबाकी से कहते हैं कि प्राथमिक स्कूल का समय बच्चे की रुचि को समझने का होता है लेकिन हमारे यहां पूरा दिन भोजन की उम्मीद और उसकी सुंगध में ही बीत जाता है। उनका मामना है कि ये योजना तत्काल प्रभाव से बंद होनी चाहिए। बच्चों को भोजन उपलब्ध करवाने से बेहतर है कि सरकार ऐसी कोई नीति बनाए जिससे उनके अभिभावक आर्थिक तौर पर मजबूत हों और वे उन्हें बेहतर शिक्षा के लिए तैयार करने में मददगार साबित हो सकें।

मुरादाबाद के ग्रामीण हिस्से में स्कूल के प्रबंधक आर.सी.शर्मा का कहना है कि शिक्षा के स्वरुप में बदलाव आया है लेकिन अब भी पूरी तरह से ये वो शिक्षा व्यवस्था नहीं है जो एक बेहतर भविष्य की गारंटी कही जा सके। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के तहत बच्चों को केवल ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान तो वर्तमान शिक्षा दे रही है लेकिन हमें बच्चे के दिमाग को बचपन में ही पढ़ने की आवश्यकता है।

नौकरीपेशा दिनेश कुमार सैनी का कहना है कि शिक्षा की हालत बहुत अच्छी नहीं है, विशेषकर उन राज्यों में जहां की घनी आबादी है, शिक्षा को लेकर बच्चों को एक अच्छा माहौल मिलना चाहिए जिसमें वे पूरे मन से अपना अध्ययन कर सकें। नौकरीपेशा प्रभूसिंह राठौड़ का कहना है कि ये सही है कि आज शिक्षा बच्चों को इतना काबिल बनाने की ताकत रखती है कि वो विदेश तक पहुंच रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होना चाहिए कि वे अपने देश के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी को समझते हुए यहीं रहें और उनके सपने हम अपने ही देश में पूरे कर पाएं...। निश्चित तौर पर अभिभावकों के लिए बच्चों को पढ़ाना बेहद मुश्किल होता जा रहा है, कम से कम पढाई पर खर्च को नियंत्रित किया जाना चाहिए। ठेकेदार मोहम्मद फुरकान का कहना है कि हम अपने बच्चों को निजी स्कूलों में नहीं भेज सकते, बेहतर हो कि सरकारी स्कूल में ही निजी स्कूल की भांति शिक्षा की व्यवस्था लागू कर दी जाए। गरमी के दिनों में मुरादाबाद में तपन अधिक हो जाती है और सरकारी स्कूलों में बिजली और पंखों की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। ऐसे में बच्चे क्या और कैसे पढ़ पाएंगे। बच्चों के लिए पढ़ाई बहुत मुश्किल होती जा रही है, सरकार को पढ़ाई की व्यवस्था सुधारने पर ध्यान देना चाहिए।

अमरोहा जिले के हसनपुरकलां में स्कूल संचालक शिवकुमार का कहना है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का एक सिस्टम है और वो सालों से है, उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। वर्तमान शिक्षा में अंग्रेजी अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन हमारे यहां एक बड़ा हिस्सा इससे अब भी दूर है। अंग्रेजी के बिना जब अच्छे भविष्य की कल्पना नहीं हो सकती है तो सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी का भी इसी तरह उन्नयन किया जाना चाहिए। अभिभावकों की परेशानी को कोई समझना नहीं चाहता, बेहतर है उन्हें इस महंगी शिक्षा से राहत मिल जाए।

अमरोहा के योगेंद्र योगी और मोहम्मद आसिफ, संभल जिले के बइजोई निवासी जगदीशचंद्र शर्मा, हेमलता शर्मा, बिजनौर से दीपचंद्र तिवारी का कहना है कि इस दौर में पढ़ाई ही सबसे मुश्किल है, बच्चों को बेहतर शिक्षा सभी अभिभावकों का सपना होता है लेकिन ये सपना इतना महंगा है कि अब वो तेजी से हाथों से छिटकता ही जा रहा है। वर्तमान शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है।

महंगी व्यवसायिक शिक्षा का योग्य छात्रों पर प्रभाव

महंगी व्यवसायिक शिक्षा का योग्य छात्रों पर प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है, ऐसे परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है या जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए व्यवसायिक शिक्षा अभी भी एक सपने के समान ही है। गरीबी रेखा के नीचे के लोगों की बात की जाए तो उनके लिए ये ि"ाक्षा अब भी कोसों दूर है। मेरे विचार से ि"ाक्षा वो बेहतर है जो सभी के लिए हो, सभी के जीवन स्तर को उंचा उठाने का कार्य करे, लेकिन वर्तमान ि"ाक्षा में केवल उच्च वर्ग तेजी से बेहतर होने की ओर अग्रसर है जबकि उच्च–मध्यम वर्ग तथा मध्यम वर्ग के लिए चुनौतियां काफी हैं।

हमने कुछ छात्र और छात्राओं से भी बात की। ये गहरी चिंता का विषय है कि उनमें से अधिकांश के मन में ये बात भी गहरे बैठ गई कि व्यवसायिक शिक्षा यदि बेहतर जगह से नही मिल पाई या ली गई तो करियर नहीं बन पाएगा। बेहतर जगह वो उसे मानते हैं जो महानगरों में है अथवा ख्याति पा चुकी संस्थाएं। ग्रामीण हिस्से के बच्चों के शहर और महानगर निकलने का मतलब है कि उस पूरे परिवार के लिए एक बड़ी चुनौती का सामने खड़ा होना। ये भी देखा जा रहा है कि ग्रामीण अंचल के बच्चे इस बेहतर शिक्षा से दूरी बनाते जा रहे हैं, ये न तो बेहतर शिक्षा व्यवस्था के संकेत हैं और न ही एक बेहतर व्यवस्था को दर्शाता है। छात्रों ने ये भी स्वीकारा कि बेहतर शिक्षा के लिए उसका आम आदमी के नजदीक पहुंचना आवश्यक है। यही कारण है कि ग्रामीण हिस्से की प्रतिभाएं अब महानगर तक का मुश्किल सफर तय नहीं कर पा रही हैं जो कि गहरा चिंतनीय प्रश्न है। अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब छात्रों हेतु सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजना भी संचालित की गई है लेकिन सरकारों के बदलने और समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलने की चिंता छात्रों तथा अभिभावकों को वर्षभर सताती रहती है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि किसी दल विशेष की सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति की छात्रवृत्ति पहले निर्गत कर दी जाती है जबकि अन्य पिछड़े वर्ग की बाद में। कभी अन्य पिछडा वर्ग की छात्रवृत्ति पहले निर्गत कर दी जाती है तो अनुसूचित जाति और जनजाति की बाद में अथवा अनिश्चितता के दौर में। सामान्य श्रेणी के निर्धन परिवारों के बच्चों के अध्ययन हेतु सरकारी सहायता दूर की कौड़ी जैसी ही है। वैसे तो शिक्षा मौलिक अधिकार की श्रेणी में आती है और हमारे संविधान के अनुसार चौदह वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है लेकिन उसके बाद भी हमारे देश में कक्षा आठवीं तक के सभी निजी विद्यालय अभिभावकों से शुल्क ले रहे हैं और केंद्र व राज्य सरकारें मूकदर्शक बनकर इस पूरी प्रक्रिया को देख रही हैं। ऐसी स्थिति में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था से आर्थिक रुप से कमजोर लेकिन मानसिक स्तर पर योग्य छात्रों के लिए शिक्षा हासिल करना बेहद मुश्किल है। योग्य और प्रतिभाशाली छात्र–छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए देश में संविधान द्वारा प्रदत्त शिक्षा के मौलिक अधिकार का पूर्ण रुप से पालन किया जाना चाहिए और 14 वर्ष तक की निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था का विस्तार 25 वर्ष तक किया जाना चाहिए।

उच्च एवं महंगी शिक्षा का अभिभावकों पर प्रभाव

–देश की वर्तमान शिक्षा में सबसे मुश्किल उच्च शिक्षा है जो सभी के लिए सुलभ नहीं हैं। मुझे लगता है कि ज्ञानार्जन के लिए आवश्यकता इच्छाशक्ति की होनी चाहिए लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां डोनेशन, फीस, होस्टल के पैकेज तय होते हैं। अब इन पैकेज के खाके में मध्यमवर्गीय परिवार अपने आप को सहज महसूस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ अभिभावकों से चर्चा हुई उन्होंने स्पष्ट कहा कि उच्च शिक्षा के लिए मध्यमवर्गीय परिवार के सामने दो ही रास्ते होते हैं कि या तो पिता उस भारीभरकम पैकेज के लिए कर्ज करे या फिर छात्र बैंक से ऋण लेकर अपनी उच्च शिक्षा अर्जित करे। बेहतर होता कि शिक्षा सस्ती होती, सुलभ होती और सहज ही मिलने वाली होती। हमारे देश में प्रतिव्यक्ति आय वैसे ही बहुत कम है और एक परिवार के लिए अपने बच्चे को उच्च शिक्षा दिलावाना बहुत मुश्किल निर्णय होता है। इस व्यवस्था के दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं, बैंक से लिए गए ऋण की किश्तों को पूरा करने के लिए छात्र नौकरी तलाशने लगता है, उसका उच्च अध्ययन को लेकर मनोयोग ही तैयार नहीं हो पाता। यहां मुझे लगता है कि हम बच्चों को अध्ययन का एक बेहतर माहौल बनाने में भी नाकाम रहे हैं। पारिवारिक स्थितियां भी चुनौतिपूर्ण हो जाती हैं जब पिता ऋण लेकर बच्चे को उच्च शिक्षा दिलवाते हैं। बच्चे पर ये दबाव बढ़ जाता है कि उसे सबकुछ अतिशीघ्र करना है और बेहतर करना है, वो सहज होकर अपना अध्ययन नहीं कर पाता। पढ़ाई के दौरान एक दबाव समान रुप से साथ चलता है इस दबाव पर जीत दर्ज करने वाली कोई व्यवस्था हमें लागू करनी होगी। कुछ अभिभावक अपने बच्चों के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा ऋण जैसी योजनाओं के माध्यम से अपने बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करवाने का जोखिम भी उठाते हैं लेकिन जब किसी कारणवश अथवा दुर्घटनावश उक्त छात्र का निधन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अभिभावक मानसिक और व्यवहारिक रुप से टूट जाते हैं। उक्त जोखिम अभिभावकों द्वारा अपने पुत्र या पुत्री की प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है लेकिन उसके निधन पर होने पर वाली क्षतिपूर्ति का करना उक्त परिवार के लिए नामुमकिन है और शिक्षा ऋण के भुगतान का बोझ भी उसको अवसाद और आत्महत्या जैसी स्थिति के लिए विवश करता है अतः उच्च शिक्षा में शिक्षा ऋण से अभिभावकों को मुक्त करना होगा तभी अभिभावक और अध्ययनरत छात्र का मानसिक तनाव कम होगा। शिक्षा ऋण जैसी योजनाओं से निश्चित रुप से प्रतिभाशाली और योग्य छात्र–छात्राओं का भविष्य मुश्किल में घिर जाता है।

तनाव, मानसिक अवसाद, आत्महत्या

भारतीय परिवेश में देखें तो विशेषकर उच्च शिक्षा को लेकर एक बूम जैसा आता है। हम कहां फेल हो रहे हैं हमें वो भी समझने की आवश्यकता है। हम बच्चों को समय पर समझ नहीं पा रहे हैं, हम उनके व्यवहार पर बात नहीं करते, हम उनके पढ़ाई के प्रति रुझान और विषय के प्रति लगाव को भी समझना नहीं चाहते। इसके पीछे सामान्य रुप से पारिवारिक और आर्थिक परिस्थितियां की रस्साकसी होती है, लेकिन जहां स्थितियां ठीक हैं वहां भी परिवार ये जानने की कोशिश कम ही करते हैं कि बच्चे का लगाव किस दिशा में है। सालों से हम एक ही शिक्षा व्यवस्था को लेकर जीते आ रहे हैं, हम सोचते हैं कि हमारे यहां बच्चे क्या चाहते हैं ये तय करने की जिम्मेदारी परिवार के बड़े

सदस्यों की है और होता भी यही आ रहा है। हम उस बूम की बात करें तो परिवार ये तय करने लगे कि हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, बच्चे से पूछा नहीं जाता और महंगी सी शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा उसे कर्ज लेकर बना दिया जाता है। बावजूद इसके अवसाद की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, बच्चे का तनाव बढ़ता है। वो ये तय नहीं कर पाता कि आखिर जिस विषय में उसे पढ़ने की रुचि नहीं है उसे वो ही क्यों पढ़ना है, क्यों उसे वही भविष्य बनाना है जो उसे पसंद नहीं है। परिवार का दबाव बढ़ता जाता है और बच्चे का तनाव भी। ऐसी स्थितियां भी निर्मित हो जाती हैं जब ये अवसाद की स्थिति चरम सीमा पार कर जाती है और बच्चा आत्महत्या जैसे घातक कदम उठा लेता है। मुझे लगता है ये कोई बेहतर शिक्षा व्यवस्था नहीं है, हालांकि बदलाव आ रहा है लेकिन उसकी गति बहुत ही धीमी है और जहां तक शिक्षा में ये बूम एक पेशेवर तरीका है, एक बाजार है जो हमें बदलना पड़ेगा। जब तक इस अहम बिंदू पर कार्य नहीं किया जाएगा, गहन चिंतन नहीं किया जाएगा तब तक ये हम ये वीभत्स सी सच्चाई से जूझते रहेंगे।

वर्तमान शिक्षा में प्रतिभाशाली छात्रों के उन्नयन तथा अभिभावकों के आर्थिक बोझ को कम करने हेतु सुझाव

1. मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा छात्रों को किसी भी राज्य में किसी भी शिक्षा संस्थान में प्रवेश व छात्र के संपूर्ण विवरण को ऑनलाइन प्रदर्शित करने के लिए एक वेबपोर्टल लांच किया जाना चाहिए।

2. प्रत्येक छात्र को एक यूआईडी प्रदान की जाए।

3. ये यूआईडी छात्रों की आधार संख्या होगी इसके उपरांत, छात्र–छात्रा को कोई भी अनुक्रमांक या नामांकन की जरुरत नहीं है। छात्र द्वारा संबंधित संस्थान द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण किया जाए और पंजीकरण तभी संभव हो जब आधार कार्ड का विवरण आधार नंबर डालते ही स्वयं ही प्रदर्शित हो जाए। उक्त पोर्टल आधार से लिंक किया जाए।

4. वेबपोर्टल पर प्रत्येक छात्र का यूआईडी आधार संख्या के साथ–साथ उक्त पाठयक्रम में प्रवेश की तिथि और ऑनलाइन पंजीकरण संदर्भ संख्या स्वतः ही ऑनलाइन जनरेट होने की व्यवस्थ होनी चाहिए जिससे कोई भी शिक्षण संस्थान नियमों के शतप्रतिशत पालन के दायरे में आ सके। पूरे देश में एक ही निर्धारित समय में प्रवेश व परीक्षाओं का संचालन करने की व्यवस्थ हो यदि पाठयक्रम के माध्यम में कोई स्थानांतरण होता है तो ऑनलाइन टिप्पणी दर्ज करने की व्यवस्था हो।

5. संपूर्ण देश में एक समान पाठयक्रम और एक समान शैक्षिक सत्र की व्यवस्था को सुचारु करने व अध्ययन करने के उपरांत एक समान मूल्यांकन अथवा राष्टीय परीक्षा नियामक अधिकरण का गठन किया जाए। इसके दायरे में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा और तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा भी होनी चाहिए।

6. शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवसर की समानता का अधिकार जाति और धर्म के बंधन से परे सभी को मिलना चाहिए। उच्चवर्गीय (दस लाख प्रतिवर्ष आय से अधिक) अभिभावकों को छोडकर अन्य समस्त अभिभावकों के बच्चों के शिक्षण हेतु संपूर्ण देश में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। उक्त शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत राज्य व केंद्र सरकार का शिक्षा पर व्यय बढ़ना स्वाभाविक है यदि निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने में यदि सरकार को कोई आर्थिक समस्या है तो तात्कालिक रुप से अध्ययन पूर्ण करने के उपरांत जब उक्त छात्र या छात्रा एक सफल उदयमी बन जाए अथवा नौकरी प्राप्त कर ले, उसकी शिक्षा व्यवस्था पर खर्च समस्त धनराशि को बिना ब्याज के उसके द्वारा आसान किश्तों में चुकाने की व्यवस्था हो और किसी दुर्घटना का शिकार होने पर उक्त धनराशि बीमा कंपनियों द्वारा जोखिम सुरक्षा के तहत आनी चाहिए।

(...जैसा कि आदर्श शिक्षा नीति पर सुझावों की किताब 'आओ देश गढ़ें' के लेखक बालादत्त शर्मा ने उल्लेखित किया है)

– पत्रकार संदीप कुमार शर्मा का मानना है कि बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा के कुछ और आगे बढ़कर भी सोचना होगा। शिक्षा तो हासिल हो जाती है लेकिन रोजगार के अवसर मुहैया नहीं हो पाते। बेहतर होगा कि देश में सबसे पहले आरक्षण का वर्तमान स्वरुप बदलने की आवश्यकता है। सरकार चाहे तो आर्थिक रुप से पिछड़े सभी वर्गो के लिए आरक्षण लागू कर सकती है जिससे सभी जाति और धर्म के मध्यमवर्गीय, निम्न मध्यमवर्गीय और गरीब परिवारों की राह आसान हो सकती है। उनका मानना है कि सरकार को पूरे देश में छात्राओं के लिए प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क कर देनी चाहिए, विशेषकर जिन परिवार के यहां केवल बेटियां हैं उन्हें कुछ अधिक सुविधाएं मुहैया करवानी चाहिए इससे महिला साक्षरता का प्रतिशत निश्चित बढ़ेगा जो कि वर्तमान विचारणीय प्रश्न है। भारत सरकार की जनगणना 2011 के आंकड़ों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि विगत दशकों से अभी तक हमारी समस्त शिक्षा नीतियां महिलाओं की साक्षरता दर को शत–प्रतिशत सफल बनाने में असफल रही हैं।

निष्कर्ष

हमें एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहिए जो हमारे बच्चों और भावी पीढ़ी को सही और आसान दिशा प्रदान कर सके। हम एक ऐसी दिशा की ओर बढ रहे हैं जो बहुत मुश्किल है लेकिन हमें लगता है कि सुधार के रास्ते अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं, सुधार संभव है। हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी कभी नहीं रही लेकिन व्यवस्था के कूचक्र में उलझकर प्रतिभाएं मुश्किल राह पर पहुंच जाती हैं। इससे भविष्य कठिन है। देश में शिक्षा के बाद के रास्ते भी बेहद कठिन हैं उन्हें आसान बनाना होगा। बेहतर अवसर न मिलने के कारण ही छात्र विदेश रवाना हो जाते हैं। हमें अपने बच्चों के लिए न केवल एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था बनानी चाहिए बल्कि उन्हें अपने ही देश में उनके लिए रोजगार के बेहतर अवसर भी तैयार करने होंगे। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के कारण उत्पन्न हो रही उपरोक्त वर्णित सामाजिक कुरीतियों को दूर करने तथा शिक्षा को सामान्य जनमानस तक पहुंचाने हेतु शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक प्रतीत होता है। ऐसी

स्थितियों में नई शिक्षा नीति को तैयार करने में समस्त पहलूओं पर चिंतन एवं विचार–विमर्श करना सभी नीति नियंताओं की नैतिक जिम्मेदारी भी है। समाज में आदर्श शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करने के उपरांत ही देश में साक्षरता की दर को बढाया जा सकता है। शिक्षा का स्वरुप नितांत सरल, स्वाभाविक, नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण, व्यावसायिक एवं व्यवहारिक होना चाहिए।

Corresponding Author

Kamla*

Research Scholar

E-Mail – kamla.sandeep031@gmail.com